राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेंगी बड़ी सौगातें

हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन के सम्पूर्ण सशक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा, शिखर अग्रवाल, कुलदीप रांका, श्रेया गुहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से बराबर सम्पर्क रखते हुए विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगातें देने की प्रभावी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5 हजार 500 फार्मपौण्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी है। इसी प्रकार 2 हजार किलोमीटर पाइपलाइन, 5 हजार किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, एक हजार किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3 हजार किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी। शर्मा ने कहा कि सरकार कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पम्प की स्थापना के लिए 15 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई हेतु एक दीर्घकालिक समाधान है। सरकार द्वारा 15 हजार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही 1 हजार लाभार्थियों को कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे।

इस अवसर पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ-साथ एक हजार नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि देते हुए 183.22 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मिस फ्रांसिस का देहांत

जयपुर। सेंट जेवियर स्कूल की वरिष्ठतम पूर्व टीचर मिस एम.फ्रांसिस का मंगलवार को देहांत हो गया। वे संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल जयपुर के अवेदना आश्रम में रहती थीं।

उनकी अंतिम यात्रा बुधवार को तीन बजे अवेदना आश्रम से रवाना होगी और घाटगेट स्थित चर्च पर साढ़े तीन बजे पहुंचेगी।

खाते से पैसे निकाले

जयपुर। मालवीय नगर थाना इलाके में बैंक कर्मचारी बनकर युवक को फोन कर किश्त की राशि जमा करने के नाम पर एटीएम की जानकारी लेकर उसके खाते से 75 हजार रुपए निकाल लिए।

जिंदा भ्रूण को मृत बताकर प्री-मैच्योर डिलीवरी की

एम.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व कंट्रोलर और जनाना अस्पताल के अधीक्षक पर 5.20 लाख रुपए का हर्जाना

- अदालत ने इस मामले में शिशु की मौत को अस्पताल की गंभीर लापरवाही माना है

जयपुर। जयपुर महानगर प्रथम की स्थाई लोक अदालत ने गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु बताकार प्री-मैच्योर डिलीवरी करने और बाद में शिशु की मौत को गंभीर लापरवाही माना है। इसके साथ ही अदालत ने विपक्षी एमएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व कंट्रोलर और जनाना अस्पताल के अधीक्षक पर 5.20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने कहा कि विपक्षी हर्जाना राशि का भुगतान परिवादी को तीस दिन में करें। लोक अदालत के अध्यक्ष मनोज कुमार सहारिया व सदस्या सीमा शार्दुल ने यह आदेश बीना मीना के प्रार्थना पत्र पर दिए।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विजी अग्रवाल ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान प्रार्थिया ने जनाना अस्पताल की देखरेख में इलाज शुरू करवाया। उसकी एक नवंबर 2023 को अल्ट्रा सोनोग्राफी की, जिसमें 25 सप्ताह के भ्रूण की मृत्यु होना बताया। जबकि प्रार्थिया ने कहा कि उसे गर्भ में भ्रूण की हरकत महसूस हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कहा कि तत्काल भ्रूण नहीं निकाला तो संक्रमण होने से उसकी जान जा सकती है। इसके बाद 9 नवंबर 2023 को इंजेक्शन देकर उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी करवाई गई। इसमें उसने जीवित शिशु को जन्म दिया और उसे बच्चा वार्ड में भेजना बताया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि डिलीवरी के करीब तीन घंटे बाद उसे बताया कि प्री मैच्योर डिलीवरी के चलते शिशु की मृत्यु हो गई है। इस पर अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर क्षतिपूर्ति राशि देने की गुहार की। इसके जवाब में अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया कि मरीजों की भीड और अधिक कार्य होने के कारण सोनोग्राफी बदलने से इनकार नहीं किया जा सकता। यूनिट के डॉक्टर ने सोनोग्राफी पर ही प्रसव का निर्णय लिया था। शिशु को बचाने का हर संभव प्रयास भी किया गया था और उसे पहले एनआईसीयू में भर्ती करने के बाद वेंटीलेटर पर भी रखा गया, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में उनकी ओर से लापरवाही नहीं बरती गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अस्पताल पर हर्जाना लगाया है।

महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ए.सी.बी. ने मुकदमा दर्ज किया

जे.जे.एम. घोटाले में जोशी सहित 20 आरोपियों के नाम

- इसी मामले में ई.डी.भी कर रही है जांच, जोशी के नजदीकी संजय बड़ाया और फर्म प्रोपराइटर की हो चुकी है गिरफ़्तारी

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस सरकार में पीएचईडी मंत्री रहे महेश जोशी पर ईडी के बाद राजस्थान ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी जल जीवन मिशन में घोटाले में जोशी सहित 20 लोग और दो फर्मों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इनमें पीएचईडी के अधिकारियों, पीएचईडी के ठेकेदार और निजी व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं।

एसीबी के डीजी डॉ. रविप्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशनाराम की रिपोर्ट के आधार पर जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों के संबंध में 20 लोगों और दो फर्मों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसकी जांच एसीबी की विशेष शाखा के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह को सौंपी गई है। एसीबी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पूर्व मंत्री महेश जोशी, जल जीवन मिशन के वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा, पीएचईडी के तत्कालीन मुख्य अभियंता रामकरण मीणा, दिनेश गोयल, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता, रमेश चंद मीणा, अरुण श्रीवास्तव, परितोष गुप्ता, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अजय कुमार सिंघानी, विकास गुप्ता, महेश प्रकाश सोनी, भगवान सहाय जाजू, जितेंद्र शर्मा, विशाल सक्सेना, मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवेल कंपनी, शाहपुरा के प्रोप्राइटर महेश मित्तल, फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी, शाहपुरा, श्रीश्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोप्राइटर पदमचंद जैन, फर्म श्रीश्याम ट्यूबवेल कंपनी, शाहपुरा, इरकॉन इंटरनेशनल के ऑफिस सहायक मुकेश पाठक, जोशी के नजदीकी संजय बड़ाया, किशन गुप्ता, तपन गुप्ता, नमन खंडेलवाल सहित अन्य के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

इससे पहले जल जीवन मिशन घोटाले में अवैध रूप से धन के लेन-देन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले में पदमचंद जैन, महेश मित्तल, पीयूष जैन सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी की थी। इसी मामले में सीबीआई ने भी पीएचईडी के अधिकारियों व अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। अब एसीबी ने महेश जोशी सहित 20 लोगों और दो फर्मों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

यह मामला एसीबी ने खोला था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन के बिल पास करने की एवज में रिश्वत का लेन-देन करते ठेकेदार और पीएचईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि कई जगहों पर बिना पाइप लाइन बिछाए ही भुगतान कर दिया गया। इसके साथ ही हरियाणा से चोरी के पाइप बिछाने की बात भी सामने आई थी। अब एसीबी आरोपियों को कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है।

प्रदेश के पूर्ण विकास के लिए भाजपा ही जरूरी : भजनलाल

- मुख्यमंत्री लगातार ले रहे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी फीडबैक
- उप चुनाव में कांग्रेस के जातिवाद पर भारी भाजपा का विकास का एजेण्डा
- 'कांग्रेस राज में घोटालेबाजों और माफियाओं ने मचा रखी थी लूट'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सात विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वे दिन की शुरुआत उप चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ, मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सैकड़ों पदाधिकारियों से फोन पर बातचीत करके करते हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर उप चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस के जातिवाद के एजेण्डे पर हमारी सरकार का विकास का एजेण्डा भारी है। उन्होंने कहा कि दस महीने के छोटे समय में हमने रिकॉर्ड काम किए हैं जिससे कांग्रेस की नींव हिल चुकी है और जनता का हमारी सरकार पर विश्वास जमा है। जिन मुद्दों पर कांग्रेस वर्षों तक राजनीति करती रही, हमारी डबल इंजन सरकार उनसे संबंधित समझौते कर तेजी से उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राइज़िंग राजस्थान से पहले ही हमारी सरकार ने 18 लाख करोड़ के निवेश एमओयू किए हैं और इन एमओयू को धरातल पर लाने के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित होकर कार्य कर रही है, ये निवेश राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पेपर लीक जैसे मामलों में एसआईटी ने 190 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस राज में किस कदर माफियाओं और घोटालेबाजों ने लूट मचा रखी थी। उन्होंने कहा कि हम दिखावे के बिना निरंतर जन कल्याण के कार्य करते हैं, जबकि कांग्रेस काम का नाम करने में भी बेईमानी करती है। उप चुनाव में कांग्रेस के बागी ही अपने प्रत्याशियों को निपटाएंगे।

कालवाड़ महाविद्यालय में बढ़ी प्रवेश तिथि

जयपुर। कैबिनेट मंत्री झोटवाड़ा के विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अथक प्रयासों और समर्पण से युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कालवाड़ महाविद्यालय में प्रवेश की तिथियों को बढ़ा दिया गया है, जिससे अब भी इच्छुक छात्र दाखिला ले सकते हैं। यह कदम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें शिक्षा के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार युवाओं की शिक्षा और विकास के लिए समर्पित है। यह महाविद्यालय झोटवाड़ा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और विजन से राजस्थान की भाजपा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि क्षेत्र के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

पर्याप्त मानव संसाधन नहीं रखने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की सिफारिश

सरकारी योजनाओं से भी असम्बद्ध होंगे

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को कहा है कि संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाकर सभी अस्पतालों की जांच की जाए और वर्ष 2010 के प्रावधानों के तहत उचित मानव संसाधन नहीं रखने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आयोग ने कहा कि संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद मानव जीवन के साथ खिलवाड करने वाले अस्पतालें को चिरंजीवी योजना सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं से भी डी-लिस्ट किया जाए। आयोग ने भवानीमंडी के निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के मामले में उसके पिता को पांच लाख रुपए की मुआवजा राशि देने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह इसमें से ढाई लाख रुपए की राशि दोषी अस्पताल नवजीवन हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंधन या दोषी चिकित्सकों से वसूल कर सकती है। आयोग सदस्य जस्टिस आरसी झाला ने यह आदेश आशीष पारेता के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि दोषी अस्पताल की शिशु रोग इकाई को बंद करने, अस्पताल प्रबंधन पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाने और चिरंजीवी योजना से डी-लिस्ट करने मात्र से परिवादी के आठ साल के बेटे की मौत से हुई क्षित की पूर्ति संभव नहीं है।

परिवाद में बताया गया कि 25 जनवरी, 2023 को उसके आठ साल के बेटे प्रहल पारेता के पेट दर्द होने पर उसे नवजीवन अस्पताल, भवानीमंडी लेकर गए। अस्पताल में पूछने पर पता चला कि यहां बच्चों के डॉक्टर शैलेन्द्र पाटीदार हैं। वहीं वहां मौजूद दूसरे चिकित्सक कुलदीप सिंह ने इलाज करना शुरू कर दिया। दो घंटे बाद कुलदीप सिंह के स्थान पर डॉ. हरिवल्लभ ने आकर इलाज किया और डॉ. शैलेन्द्र पाटीदार का थोडी देर में आना बताया। इसके बाद दोपहर में हरिवल्लभ ने बताया कि डॉ. पाटीदार के शादी में जाने के कारण वे अस्पताल नहीं आ सकते हैं। इस पर वे बच्चे को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल ले गए। इस दौरान रास्ते में उसने दम तोड दिया। परिवाद में बताया गया कि हरिवल्लभ एमबीबीएस चिकित्सक ही नहीं है। ऐसे में अयोग्य चिकित्सक के इलाज के कारण बच्चे की मौत हुई है। मामला आयोग में आने के बाद राज्य सरकार की ओर से अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई कर उसकी जानकारी आयोग को दी गई। इस पर आयोग ने राज्य सरकार को सभी अस्पतालों के संबंध में विस्तृत सिफारिशें की हैं।

शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल पहले शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिन्दुओं पर दिए निर्देशों की पालना को लेकर राज्य सरकार से 11 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने 21 मई 2012 को राज्य सरकार को 16 बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे। इसके तहत हर वार्ड में सौ सफाई कर्मचारी लगाने, सप्ताह के हर दिन सफाई करने, सिंगल टियर सिस्टम से सफाई, कचरा पात्र लगाने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और चार मोबाइल मजिस्ट्रेट सहित अन्य निर्देश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने इन निर्देशों की पालना को लेकर हर तीन माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

परीक्षा स्थगित

जयपुर। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने शिक्षा शास्त्री के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की सात नवंबर से चौदह नवंबर तक चलने वाली परीक्षा में आंशिक संशोधन किया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. शंभु कुमार झा ने बताया कि प्रदेश के 42 केंद्रों पर दो पारियों में होने वाली परीक्षा में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के चलते स्थगित किया गया है। झा ने बताया कि अब यह परीक्षा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व निर्धारित समय और परीक्षा केंद्र पर 16 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार इंटीग्रेटेड शास्त्री-शिक्षा शास्त्री की 13 नवंबर को होने वाली परीक्षा 23 नवंबर को होगी।

जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों एवं पहल पर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके। अब राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। योजना को गति देने के लिए 658.12 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौडगढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केकड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्री गंगानगर एवं उदयपुर के 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रूपये की 137 कार्यादेश जारी किये जायेगे। इन स्वीकृतियों से ना केवल जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा जो कि हर घर जल के सपने को साकार करेगा।

भाजपा में परिवार भाव के साथ एकजुटता से किया जा रहा है कार्य : श्रवण सिंह बगडी

- केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित 17 मंत्री, विधायक और भाजपा पदाधिकारी 6 नवम्बर को रहेंगे प्रवास पर

जयपुर। भाजपा प्रदेश के उपचुनावों को लेकर पूर्णरूप से सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जहां हर उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चुनावी रणनीति तय कर रहे है, वहीं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विकास के नाम पर आमजन से मतदान की अपील भी कर रहे है। इधर दूसरी ओर भाजपा पदाधिकारी, कैबिनेट के मंत्री सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे है। संगठन स्तर पर भाजपा का एक-एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता चुनावों में जुटा हुआ है। भाजपा प्रदेश कार्यालय से महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और उनकी टीम लगातार उपचुनावों में प्रवास कार्यक्रमों के साथ क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय जननेताओं को आमजन के बीच भेज रहे है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर नियमित रूप से चुनाव प्रबंधन के साथ प्रवास कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा सभी सातों सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कराएगी। भाजपा में कार्यकर्ता से लेकर आमजन एकजुट होकर कमल के लिए कार्य कर रहे है। भाजपा में एकजुटता नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस में भितरघात देखने को मिल रहा है। भाजपा सरकार के मंत्रीगण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 10 माह में किए ऐतिहासिक कार्यों को जनता के बीच पहुंचा रहे है, फिर चाहे वो बजट घोषणाएं हो या फिर रोजगार सृजन के लिए राइजिंग राजस्थान 2024 की कार्य योजना। मुख्यमंत्री शर्मा विकसित राजस्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और उनके विकास कार्यों के आधार पर भाजपा प्रदेश की सभी सातों सीट जीतेगी।

बगडी ने कहा कि भाजपा में परिवार भाव के साथ काम किया जाता है, भाजपा पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता और आमजन मिलकर चुनाव लड़ रहे है। ऐसे में उपचुनावों के माहौल को देखते हुए कांग्रेस भाजपा के सामने कहीं भी नजर नहीं आ रही, माहौल भाजपा के पक्ष में है और निश्चित रूप से सभी प्रत्याशी जीतेंगे।

श्रवण सिंह बगडी ने बताया कि बुधवार 6 नवंबर को खींवसर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, राज्य सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड और भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल प्रवास पर रहेंगे। इसी तरह रामगढ में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, गुजरात योग बोर्ड के चैयरमैन शीशपाल, विधायक भागचंद टांकडा, झुंझुनूं में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां, सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती और सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, दौसा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभूलाल सैनी, सलूंबर में मंत्री जोराराम कुमावत, विधायक सुरेंद्र सिंह, दीप्ति माहेश्वरी, समाराम गरासिया तथा चौरासी में मंत्री बाबूलाल खराडी प्रवास पर रहेंगे।

समृद्ध विरासत और परम्पराओं का प्रदेश है राजस्थान : देवनानी

- विधान सभा अध्यक्ष देवनानी पहुँचे सिडनी

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सिडनी में आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के सम्मेलन की डेलीगेट ब्रीफिंग में भाग लिया।

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चार देशों की यात्रा के दौरान मंगलवार को सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) पहुँचे। देवनानी का सिडनी पहुँचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। देवनानी ने सिडनी में आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के सम्मेलन की डेलीगेट ब्रीफिंग में भाग लिया। देवनानी ने सम्मेलन में मौजूद उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडू सहित भारत के विभिन्न प्रदेशों के विधान सभा अध्यक्षगण और सांसदगण से मुलाकात की।

इस मौके पर देवनानी ने कहा कि राजस्थान प्रदेश की अपनी समृद्ध विरासत, परम्पराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विशिष्ट पहचान है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीले और जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर के भव्य दुर्ग देशी तथा विदेशी सैलानियों के लिए पंसदीदा स्थान है। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रति दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते है। देवनानी इस अध्ययन यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करने के साथ संसदीय प्रतिनिधिगण से लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्षगण एक मंच पर एकत्रित होकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विषयों पर संवाद करते है। इस बार का राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ का सम्मेलन आस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवम्बर तक हो रहा है। संसदीय संघ का यह 67वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अध्यक्ष देवनानी के साथ विधान सभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा भी गये है।